डाक पंजीयन क्रमांक-म.प्र./भोपाल/357/2018-20

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 जनवरी, 2020, डिस्पेच दिनांक 16 जनवरी, 2020

| वर्ष 63 | अंक 16 | भोपाल | 16 जनवरी, 2020 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/– | आजीवन शुल्क 1500/– |

सहकारिता आंदोलन को गतिशील बनाया जाएगा

राष्ट्रीय आवास संघ की बैठक में सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मध्यप्रदेश में सहकारिता आंदोलन को बहुत क्षति पहुँची है। उन्होंने कहा कि आगामी एक–डेढ़ वर्ष में सहकारिता आंदोलन को तेज किया जाएगा। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ के चुनाव भी शीघ्र कराये जाएंगे। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने की।

अपेक्स बैंक में आयोजित बैठक में मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि राज्य सहकारी आवास संघ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिये उसके कार्यक्षेत्र एवं गतिविधियों का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास निर्माण, शासकीय आवास निर्माण, शहरी विकास के निर्माण कार्य और गृह निर्माण समितियों की खाली पड़ी जमीनों पर विकास कार्य राज्य सहकारी आवास संघ के माध्यम से कराये जाएंगे। डॉ. सिंह ने राज्य आवास संघ पर बाकी जीवन बीमा निगम की ऋण राशि का उल्लेख करते हुए कहा कि गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में ऋण चुकाने के लिये अपनाई गई वन टाइम सेटलमेंट प्रक्रिया मध्यप्रदेश में भी अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में जीवन बीमा निगम से चर्चा कर ऋण प्रकरण का निराकरण किया जाएगा।

सभी राज्यों को सशक्त बनाने होंगे सहकारी आवास संघ

राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष श्री सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि सभी राज्यों में सहकारी आवास संघ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिये संघों को नये प्रोजेक्ट प्राप्त करने होंगे। उन्होंने कहा कि अब आवास संघ को अपनी ऋण देने की एजेंसी का स्वरूप त्यागना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में अनेक एजेंसियाँ काम करने लगी हैं। श्री शर्मा ने सहकारी आंदोलन में डॉ. गोविंद सिंह के योगदान की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि मध्यप्रदेश के साथ–साथ अन्य राज्यों को भी डॉ. सिंह के अनुभवों का लाभ मिलेगा।

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश राज्य सहकारी आवास संघ पर जीवन बीमा निगम का कुल 337 करोड़ रुपये ऋण बकाया है। इसमें मूल केवल 79 करोड़ रुपये है। जानकारी दी गई कि मध्यप्रदेश इस मूल की ऋण राशि का एक साथ भुगतान करने के लिये तैयार है। इसके लिये जीवन बीमा निगम से वन टाइम सेलटमेंट की कार्यवाही की जा रही है।

बैठक की कार्यवाही का संचालन राष्ट्रीय आवास संघ, नई दिल्ली के चीफ एक्जीक्यूटिव श्री एन.एस. मेहरा ने किया। बैठक में राज्य सहकारी आवास संघ के प्रबंध संचालक श्री आर.के. शर्मा सहित उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, पुडुचेरी, राजस्थान, केरल, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक आदि प्रदेशों के राज्य सहकारी आवास संघों के अध्यक्ष और प्रबंध संचालक शामिल हुए।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

सहकारिता जिन्दगी का तौर तरीका

आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर की तरह है, यदि सागर की कुछ बूंदे खराब हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता है।

– महात्मा गांधी

किसानों के लिये यूरिया गोदाम से सीधे सहकारी संस्थाओं में पहुँचायें : डॉ. गोविन्द सिंह

भोपाल। सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा है कि खाद गोदाम से सीधे सहकारी समितियों को भिजवाई जाए। समय की बचत होगी। उन्होंने कहा कि इफको द्वारा किसानों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाई जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक विपणन सहकारी समिति में योजनाओं की जानकारी आवश्यक रूप से प्रदर्शित की जाए। डॉ. गोविन्द सिंह मिन्टो हॉल में आयोजित ''कृषि विकास में सहकारिता का योगदान'' संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

खरीफ से बॉटल में मिलेगा ''नैनो यूरिया''

प्रबंध निदेशन इफको डॉ. उदय शंकर अवस्थी ने कहा कि अगली खरीफ से पहले इफको द्वारा नैनों यूरिया पहुंचाया जाएगा। इसकी विशेषता यह है कि एक बोरी यूरिया के बराबर यूरिया का तरल स्वरूप एक बॉटल में ही मिल जाएगा। यह ठोस यूरिया से अधिक प्रभावशाली होगा और इसकी कीमत भी बहुत कम होगी। उन्होंने बताया कि इसके आने पर शासन को यूरिया पर सब्सिडी भी नहीं देनी होगी। उन्होंने बताया कि इफको जैविक खाद के बाद अब जैविक कीटनाशक भी बना रहा है, जो वातावरण के लिए नुकसान देह नहीं होगा।

मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह ने कहा कि किसानों को खेती के साथ पशुपालन तथा सहायक गतिविधियों को भी अपनाना होगा जिससे वे पर्याप्त लाभ कमा सकें। उन्होंने इफको से कहा कि प्रदेश में कोल्ड स्टोरेज बनवाने तथा खाद प्र–संस्करण उद्योग स्थापित करने की दिशा में भी कार्य करें।

कार्यशाला में बताया गया कि नरवई (पराली) जलाने की समस्या से निजात के लिए अब ऐसा डी–कम्पोज़र बनाया गया है, जिसका छिडकाव करने से फसलों के ढूठ डी–कंपोज होकर खाद बन जाएंगे और मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएंगे। मंत्री डॉ. सिंह ने इफको की जैविक खाद, नैनो यूरिया, पशु–आहार आदि की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यशाला में सहकारिता के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए श्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, श्री डी.पी. गर्ग, निदेशक एवं प्रबंध संचालक मार्कफेड श्रीमती स्वाति मीणा नायक को सम्मानित किया गया।

किसानों को समृद्ध बनाकर प्रदेश में लाएंगे कृषि क्रांति : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने सतना में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के दूसरे चरण में जिले के 1134 किसानों को ऋण माफी के प्रमाण–पत्र देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में किसानों को समृद्ध बनाकर कृषि क्रांति लाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के पहले चरण में 21 लाख किसानों की ऋण माफी का वचन पूरा किया है। अब किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने के लिये काम किया जा रहा है। श्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश की 70 प्रतिशत आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी है। इसलिये सरकार कृषि के क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिये कृत–संकल्पित है।

रोजगार के क्षेत्र में मध्यप्रदेश बनाएगा इतिहास

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिये तेजी से प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि आज के नौजवान की सोच अलग है, वह इन्टरनेट से जुड़ा है, काम चाहता है, व्यवसाय चाहता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में निवेश का वातावरण निर्मित हो गया है। प्रदेश में विभिन्न उद्योग लगाये जा रहे हैं, जिनमें नौजवानों को रोजगार सुनिश्चित होगा। श्री कमल नाथ ने कहा कि युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराकर मध्यप्रदेश इतिहास बनाएगा।

सभी जिलों के विकास को प्राथमिकता

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों के विकास को प्राथमिकता दी जा रही है। जिलों में सर्वहारा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर योजनाएं और कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 129.51 करोड़ लागत के 62 विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि–पूजन किया। कार्यक्रम में दुलारी बाई, राम लघन, सियासरण सुराखी, दुर्गेश यादव, कलावती, संतोष डोहर आदि को शहरी आवास योजना के पट्टे वितरित किये गये।

सांसद श्री विवेक तन्खा ने कहा कि प्रदेश के विकास को नई दिशा देने के लिये मुख्यमंत्री ने शुद्ध के लिये युद्ध और भू–माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संदेश देकर जनहित औरविकास को नई दिशा दी है। सतना जिले के प्रभारी अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री लखन घनघोरिया ने जिले में क्रियान्वित योजनाओं की जानकारी दी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने लोगों से विकास में सहभागी बनने का आव्हान किया।

कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष सुश्री हिना कांवरे, राज्यसभा सदस्य श्री राममणि पटेल, पूर्व मंत्री श्री पुष्पराज सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री सईद अहमद, श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री राहुल सिंह, विधायक श्री सिद्धार्थ कुशवाहा, अन्य जन–प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित थे।

सोच में परिवर्तन लायें, मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलें

नये साल में मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गिनाईं सरकार की प्राथमिकताएँ

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने यहाँ मंत्रालय में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ नए वर्ष की पहली बैठक में नव–वर्ष की बधाई देते हुए सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अब एक साल पुरानी हो गई है। प्रशासनिक तंत्र को सरकार की सोच स्पष्ट हो गई है। उन्होंने कहा कि सभी ने सरकार को आजमा लिया है। उन्होंने कहा कि हर सरकार और मुख्यमंत्री की अपनी दृष्टि और कार्यशैली होती है और प्रशासन तंत्र के भी अपने तौर–तरीके होते हैं।

प्रमुख बिन्दु

- सोच में परिवर्तन लायें, मध्यप्रदेश की प्रोफाइल बदलें।
- ई–गवर्नेंस से वी–गवर्नेंस पर जायें।
- सरकार की सोच और प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तरीकों में अंतर न हो।
- सरकार जवाबदेह और मित्रवत् हो।
- हम समय नहीं बदल सकते लेकिन समय हमें जरूर बदल देगा इसलिए समय के साथ आगे बढ़ें।
- प्रदेश में विश्वास और आत्म–विश्वास का वातावरण बने।
- शासन–प्रशासन में सुधार लाना सबसे बड़ी चुनौती।
- दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से सीख लें।
- हर विभाग समीक्षा प्रकोष्ठ और विजन डाक्यूमेंट बनाए।
- केन्द्र सरकार में लम्बित योजनाओं को प्राथमिकता से लें।
- थोड़े नुकसान के लिए बड़े फायदे की अनदेखी करना ठीक नहीं।
- अन्य राज्यों में हो रहे अच्छे कामों का भी अध्ययन करें।
- उद्योग क्षेत्र में अविलम्ब त्वरित स्वीकृति देने की व्यवस्था अमल में लायें।
- अनुपयोगी जमीन के लोक हित में उपयोग के लिए भूमि प्रबंधन प्राधिकरण गठित होगा।
- एक सप्ताह में कर्मचारी आयोग काम करना शुरू करें।
- शिक्षा में गुणवत्ता सुधार प्राथमिक शालाओं से करें।
- कौशल उन्नयन की सफलता का आकलन करें।
- प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पद–स्थापना हो।
- विभागीय बजट राशि का उपयोग जनवरी, फरवरी, मार्च में करने की प्रवृत्ति से बचें।
- नकली दवाई बनाने वाली दवा कम्पनियों के विरूद्ध अभियान चलेगा।
- शुद्ध के लिए युद्ध करने की स्थिति बनना अपने आप में अप्रिय।
- मध्यप्रदेश को शुद्धता का प्रदेश बनाने के लिए प्रतिबद्ध।
- प्रदेश में माफिया का अंत होगा।
- सरकार माफिया को बर्दाश्त नहीं करेगी।
- कानून का उल्लंघन करने वाले साधारण लोगों को माफिया की दृष्टि से न देखें।
- जनजातीय समाज को उनका अधिकार देने के लिए कदम बढ़ाने होंगे।
- सबूत होते हुए गरीब लोगों से रिकॉर्ड माँगना और लकीर के फकीर बने रहने की प्रवृत्ति ठीक नहीं।
- कुपोषण मिटाना सर्वोच्च प्राथमिकता।
- पर्यटन की संभावनाओं को साकार करें।

सहकारिता विभाग के वसूली/बिक्री अधिकारियों तथा परिसमापकों के अधिकार कर्तव्य एवं कार्यप्रणाली पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण

भोपाल। सहकारिता विभाग के वसूली/बिक्री अधिकारियों तथा परिसमापकों के अधिकार कर्तव्य एवं कार्य प्रणाली पर दिनांक 26.12.2019 से 28.12.19 तक तीन दिवसीय प्रशिक्षण राज्य सहकारी संघ द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें नर्मदापुरा एवं इंदौर संभाग के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के अंतर्गत श्री श्रीकुमार जोशी, सेवा निवृत संयुक्त आयुक्त सहकारिता ने म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 85 के अंतर्गत वसूली/बिक्री अधिकारियों की कार्यप्रणाली, कर्तव्य, दायित्व निर्वहन की जाने वाली प्रक्रिया एवं अन्य संबंधित अधिकार, कृषि ऋणों की वसूली में वसूली/बिक्री अधिकारी के कर्तव्य एवं दायित्व निर्वहन की जाने वाली प्रक्रिया पर तथा श्री जे.पी गुप्ता सेवानिवृत्त अपर आयुक्त सहकारिता, भोपाल ने गैर कृषि वसूली तथा शासकीय शास्तियों की वसूली की कार्यवाही तथा परिसमापन कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन तैयार करना एवं विघटन की कार्यवाही एवं श्री भुवन गुप्ता, तलसीलदार, म.प्र. निर्वाचन आयोग ने भू–राजस्व संहिता अंतर्गत वसूली अधिकारियों के कर्तव्य दायित्व तथा अतिरिक्त तहसीलदार की शास्तियां, तहसीलदार के द्वारा वसूली हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विस्तार से बताई। श्री डी. के.सक्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा समन तथा नोटिस की तामिली, शास्ति डिक्री एवं निष्पादन की कार्यवाही पर विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण की रूपरेखा पर प्रचार्य ने प्रकाश डाला। सत्र समन्वयक श्रीमती मीनक्षी बान थी।

गांधी जी ने गांव का विकास सहकारिता के माध्यम से करने पर बल दिया

जबलपुर। गॉधी जी ने गॉव का विकास सहकारिता के माध्यम से करने पर बल दिया। गांधीजी ने भारतीय समाज और गांव का अध्ययन सूक्ष्मता से किया ओर पाया कि सहकारिता उनके सादगीपूर्ण जीवन के काफी करीब है यह बात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अशोक सिंघई जी ने कही।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त सहकारिता श्री शिवम् मिश्रा जी ने कहा कि राष्ट्रपिता ने अपने जीवन में सदा सहयोग ओर सहकारिता की भवना को महत्व दिया था। सहकारिता की भावना को एक बड़ी शक्ति समझते थे। उनका सोचना था की सहकारिता में जहॉ एक ओर एकता निहित है वहीं दूसरी ओर सहकारिता सफलता का एक सशक्त माध्यम है। उन्होंने महासागर से सहकारिता से तुलना करके उसके महत्व प्रतिपादित किया था। गांधी जी ने कहा था कि बिखरे हुए पानी की बूंदे सूख जाती है लेकिन वे ही बूंदे एक दूसरे से मिलकर महासागर बनाती है जिसके विशाल वक्ष पर बड़े बड़े जहाज चलते है।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित, जबलपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित गॉधी दर्शन एवं सहकारिता विषय पर आयोजित सेमीनार संपन्न हुआ कार्यक्रम में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने भी उनके सिद्धान्तों ओर अमूल्य योगदान पर अपने विचार व्यक्त किये। इस दौरान एस.सी. दहायत, अंकेक्षण अधिकारी उपभोक्ता संघ के सहायक प्रबंधक श्री पांडे जी ने भी अपना संबोधन व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन जिला संघ के प्रबंधक श्री राकेश वाजपेई ने किया। कार्यक्रम के दौरान सहकरिता विभाग में कार्यरत श्रीमती ममता धनोरिया के दिवंगत पति की आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनिट का मौन रखा गया। आभार प्रदर्शन सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के श्री एन.पी. दुबे द्वारा किया गया। श्री शोभित ब्यौहार श्री पीयूष राय व श्री कैलाश कहार का सहयोग सराहनीय रहा।

कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता एवं महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न पर कार्यशाला

भोपाल। सहकारिता विभाग की महिला अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता एवं महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न पर कार्यशाला का आयोजन दिनांक 30 दिसम्बर 2019 को संघ मुख्यालय में किया गया। कार्यशाला में श्रीमती शालिनी दीक्षित, अतिरिक्त महानिदेशक (AIG) महिला अपराध शाखा मुख्यालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 एवं आईसीसी एवं एलसीसी कमेटी की अनुशंसा, प्रावधानों एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला। श्रीमती सृष्टि उमेकर ने कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता एवं महिलाओं का लैगिंक उत्पीड़न के मनोविज्ञान का प्रभाव बतलाया। श्री पृथ्वी राज सिंहा, शिक्षा अधिकारी, केन्द्रीय श्रम कल्याण विभाग ने कार्यस्थल पर प्रभावोत्पादकता पर व्याख्यान दिया। कार्यशाला में श्रीमती गीता झा दिशोरिया, संयुक्त आयुक्त, श्रीमती कृति सक्सेना, उपायुक्त एवं श्रीमती अलका तिवारी, सहायक अयुक्त सहित 32 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री ए.के. जोशी, प्रभारी प्राचार्य एवं श्रीमती मीनाक्षी बान कम्प्यूटर प्रशिक्षक द्वारा किया गया।

सायबर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इन्दौर। सहकारिता क्षेत्र को सायबर अपराध, सुरक्षा उपाय व आई.टी. एक्ट के प्रति जागरूक करने के लिये म. प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या., भोपाल द्वारा प्रदेश की महत्वपूर्ण सहकारी संस्थाओं में सायबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर द्वारा दिनांक 8 जनवरी 2020 को इन्दौर प्रगतिशील सहकारी साख संस्था मर्या., इन्दौर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सायबर अपराध के प्रकार, तरीके व उनसे बचाव के उपाय तथा आई.टी. एक्ट के प्रावधानों की जानकारी दी गई। इससे संबंधित पाठ्य सामग्री भी वितरित की

गई। प्रशिक्षार्थियों द्वारा कार्यक्रम को उनके कार्यक्षैत्र के लिये बहुत उपयोगी बताया गया। संस्था के प्रबंधक, संचालकगण व कर्मचारियों द्वारा उत्साह से भाग लिया गया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर के कम्प्यूटर प्रशिक्षक श्री शिरीष पुरोहित द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तथा प्रशिक्षक श्री कालका श्रीवास्तव द्वारा राज्य संघ की गतिविधियों की जानकारी व आभार व्यक्त किया गया।

गांवों का विकास सहकारिता से संभव

गांधी दर्शन एवं सहकारिता विषय पर सेमीनार

खण्डवा। गांधी जी ने गांवों का विकास करने में सहकारिता से करने की पैरवी की थी और फिर यह पूरे देश में फैलता गया। गांधी जी ने भारतीय समाज और गांवों का अध्ययन सूक्ष्मता से किया और पाया कि सहकारिता उनके सादगी वाले प्रयोग के ज्यादा करीब है। यह बात शहर कांग्रेस अध्यक्ष इंदलसिंह पवार ने कही। राष्ट्रीय सहकारी संघ नई दिल्ली व म.प्र. राज्य सहकारी संघ, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर एवं जिला सहकारी संघ मर्यादित के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 18.12.2019 को सहकरी प्रबंध एवं ट्रस्टीशिप विषय पर सेमीनार आयोजित किया गया। सेमीनार में कांग्रेस नेता आलोकचंद्र चौरे,, लव

जोशी, रावत, साहित्यकार डॉ. जगदीश कैलाश हरि पटेल, देवेन्द्र जैन, विकास व्यास ने भी संबोधित किया। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर के प्राचार्य श्री निरंजन कसारा एवं शिक्षा अधिकारी के.एल. राठौर ने सदस्यों एवं कर्मचारियों को सेमीनार विषय से परिचय कराया। उप आयुक्त सहकारिता श्री के.पाटनकर एवं बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एन.यू. सिद्धीकी ने भी गांधीजी द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन संजय गांवशिन्दे ने किया। आभार प्रबंधक श्री मेहताबसिंह भदौरिया ने माना।

गांधीवादी विचार ही फलीभूत कर रहे 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की अवधारणा

मुख्यमंत्री द्वारा छिंदवाड़ा में गाँधी जी के सभा स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा है कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए गांधीवादी विचार ही वसुधैव कुटुम्बकम की अवधारणा को फलीभूत कर रहा है। ''जय जगत यात्रा'' से युवा पीढ़ी का जुड़ाव यह दर्शाता है कि गांधी जी के संदेश को देश ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में प्रसारित करना वर्तमान समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ''जय जगत यात्रा'' में शामिल हुए विदेशी पदयात्री इसका अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका यह कार्य नई पीढ़ी को सीख प्रदान करेगा। श्री कमल नाथ छिंदवाड़ा में गांधी प्रवास शताब्दी शुभारंभ समारोह के अंतर्गत गांधी जी के प्रथम नगर आगमन के सभा–स्थल के सौंदर्यीकरण कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि अफ्रीका प्रवास के दौरान उनकी मुलाकात एक देश के राष्ट्रपति से हुई। उनके कक्ष में गांधी जी की प्रतिमा का होना यह बता रहा था कि गांधी जी को भारत ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व आदर्श के रूप में मानता है। श्री कमल नाथ ने कहा कि जय जगत यात्रा का छिंदवाड़ा में आगमन होना भारतीय संस्कृति की इस नगरी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिये गांधी जी का संदेश वर्तमान में और अधिक प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री ने जय जगत यात्रा का नेतृत्व कर रहे श्री राजगोपाल एवं उनके गांधीवादी चिंतक पदयात्रियों की सराहना की।

प्रख्यात गांधीवादी चिंतक श्री राजगोपाल ने कहा कि यात्रा को अपनी बुलंदियों पर पहुँचाने में सभी साथियों का सहयोग मिल रहा है। यात्रा के दौरान बच्चों, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों का स्नेह प्राप्त हुआ है, जिससे यात्रा सफलतापूर्वक तय की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सत्य और अहिंसा के आदर्शों के समावेश के लिये छिंदवाड़ा जिला सबसे बेहतर मॉडल बन सकता है। जल पर्यटन के साथ अब शांति पर्यटन के लिए यह प्रदेश उपयुक्त प्रतीत होता है। श्री राजगोपाल ने कहा कि इस अवधारणा को मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ के नेतृत्व में साकार किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ स्थानीय कलाकारों द्वारा आयोजित भजन संध्या में भी शामिल हुए। कार्यक्रम में गांधी जी के संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए प्रख्यात गांधीवादी चिंतक श्री पी.व्ही. राजगोपाल के नेतृत्व में निकले जय जगत यात्रा के यात्रीगण विशिष्ट रूप से उपस्थित

नदी, तालाब, कुंओं के संरक्षण-संवर्धन की ठोस रणनीति बनायें

''जल जीवन मिशन'' पर कार्यशाला में मंत्री श्री पांसे

भोपाल। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री सुखदेव पांसे ने जल भवन में ''जल जीवन मिशन'' क्रियान्वयन की कार्यशाला में कहा कि ग्रामीणों को घर तक नल से जल पहुँचाने की जिम्मेदारी को मिशन के रूप में निभायें। उन्होंने कहा कि नदी, तालाब और कुओं के संरक्षण और संवर्धन की ठोस रणनीति बनायें। श्री पांसे ने कहा कि राज्य सरकार ने 'राईट टू वाटर एक्ट' के जरिये सम्पूर्ण आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की सार्थक पहल की है। इस मिशन का शत–प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों है।

मंत्री श्री पांसे ने अधिकारियों से कहा कि जल मिशन योजना के अन्तर्गत न सिर्फ लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित हो बल्कि योजनाओं से ग्रामीणों को दीर्घकालीन लाभ भी मिले। उन्होंने कहा कि योजना में आमजनों की सक्रिय सहभागिता और वित्तीय भागीदारी भी सुनिश्चित की जायेगी।

प्रमुख सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला ने कहा कि ग्रामीण परिवारों को गुणवत्तायुक्त पेयजल घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण जरूर है लेकिन बेहतर प्लानिंग से इसे सफल बनाया जा सकता है। भारत सरकार के जल एवं स्वच्छता मंत्रालय के उप सचिव श्री मनोज साहू ने कहा कि जल–गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये हर गाँव में 5 महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से गुणात्मक जल परीक्षण का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। साथ ही, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर कार्यरत जल परीक्षण प्रयोगशालाओं का चरणबद्ध तरीके से नेशनल ऐक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग केलिब्रेशन लेबोरेटरीज (NABL) से प्रमाणीकरण कराया जायेगा।

कार्यशाला में प्रमुख अभियंता श्री सी.एस. संकुले, प्रमुख अभियंता (सलाहकार) श्री के.के. सोनगरिया, जल निगम के निदेशक श्री बी.एम. सोनी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

एक हजार गौ-शालाओं का निर्माण कार्य प्रगति पर : मंत्री श्री पटेल

भोपाल। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए कहा है कि इस योजना में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक हजार गौ–शालाओं का निर्माण करने का लक्ष्य है। गौशालाओं के निर्माण कार्य तेजी से पूरे किये जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों पर अब तक 9395 लाख रूपये व्यय किये गये हैं।

मंत्री श्री पटेल ने निर्देश दिये कि मनरेगा में जल संरक्षण संरचनाओं के कार्यों को प्राथमिकता दी जाये और इन्हें समय–सीमा में पूरा किया जाये। उन्होंने 36 जिलों में पुनर्जीवन कार्यों की गुणवत्ता कायम रखने मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के इंजीनियर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाये। उन्होंने कहा कि कपिल धारा कूप और सुदूर सड़क निर्माण के कार्य भी शीघ्र पूरे करायें।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनरेगा श्रीमती शिल्पा गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में 7 लाख 20 हजार 84 निर्माण कराये गये हैं। योजना में वित्त वर्ष 2019 में 2461 करोड़ की राशि मजदूरी के रूप में भुगतान की गई है।

मैंदानी अनुभव से सरकार को लाभान्वित करें उद्योग और व्यवसाय

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ का कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज अवार्ड कार्यक्रम में संबोधन

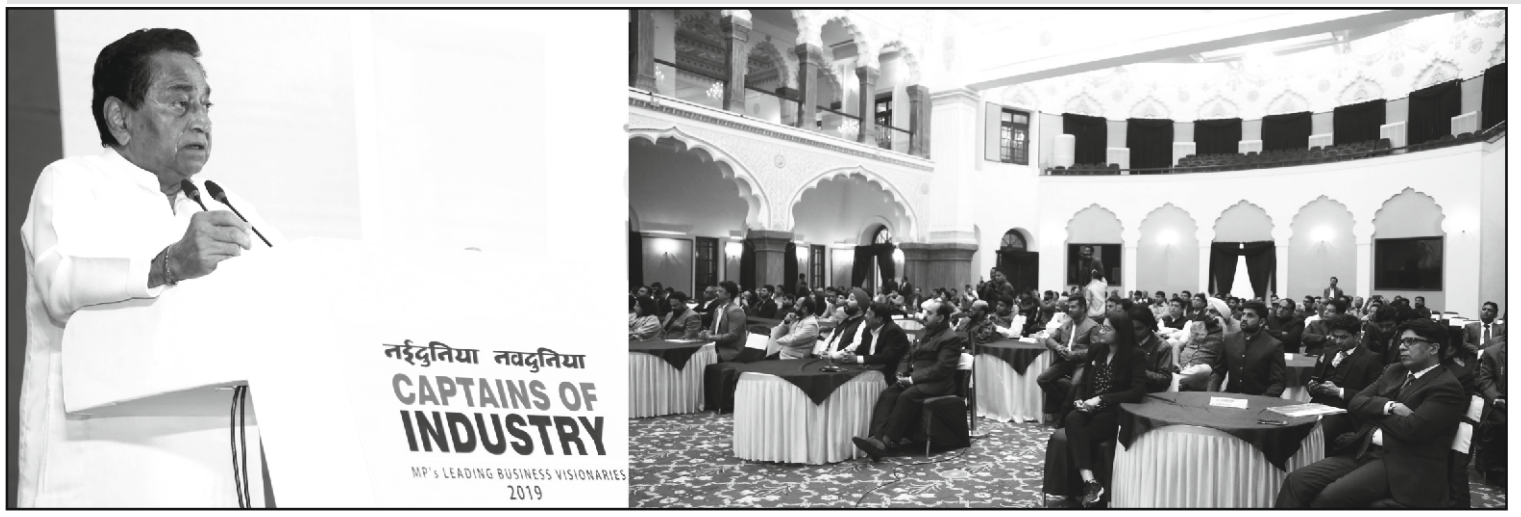

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने व्यापार और उद्योग सहित अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़े लोगों से कहा है कि वे अपने मैदानी अनुभव से सरकार को लाभान्वित करें जिससे प्रदेश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाया जा सके। श्री कमल नाथ आज मिंटो हॉल में 'कैप्टन ऑफ इंडस्ट्रीज अवार्ड' समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योग्यता की कमी नहीं है आवश्यकता इस बात की है कि हम उन्हें कैसे सहयोग दें और प्रोत्साहित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास मैदानी अनुभव उद्योग, व्यापार के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम है। इसलिए यह जरूरी है कि इस क्षेत्र के लोग अपने अनुभव राज्य सरकार से साझा करें जिससे प्रदेश को लाभ हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हर क्षेत्र में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों की आशाएँ और अपेक्षाएँ भी बढ़ रही हैं। समय के साथ बदलावों को अपनाते हुए हर क्षेत्र में हमें लोगों की उम्मीदों के मुताबिक सुविधाएँ उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, आईटी, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज से पाँच साल पहले की स्थिति से बिल्कुल अलग स्थिति है। पहले शिक्षा दिलाने के लिए संस्थान की आवश्यकता होती थी लेकिन आज हॉर्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन एजुकेशन सुविधा उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है लेकिन देश में हमारी गिनती पिछड़े राज्यों में होती है। हमें अपनी इस पहचान को समाप्त कर एक नई पहचान बनाना है। हमारा प्रयास है कि हमारे प्रदेश की तुलना अग्रणी राज्यों के साथ हो। हमारा एक नया प्रोफाइल बने, जो न केवल अपने देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केन्द्र हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक नई सोच और व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ सरकार और लोगों के सहयोग से हम अपने प्रदेश के प्रोफाइल को बदल सकते हैं।

श्री कमल नाथ ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमारी अर्थ–व्यवस्था में सुधार आता है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है और व्यापार–व्यवसाय में वृद्धि होती है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए सेवा क्षेत्र के साथ–साथ पर्यटन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बतलाई।

मुख्यमंत्री ने इस मौके पर चिकित्सा, शिक्षा एवं निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियाँ हासिल करने वाले होम्योपैथी डॉ. ए.के. द्विवेदी, डॉ. अर्पित मार्डन, श्री चंचल सोनी, श्री मनमोहन कांत समाधिया, श्री नहारु खान, श्री निशांत वत्स, डॉ. प्रमोद पी. नीमा, श्री प्रवीण दरयानी, श्री रमेश अग्रवाल, श्री रमनवीर सिंह अरोरा, डॉ. सतिंदर कौर सलूजा, श्री सिद्धांत जोशी, श्री सुधार कुमार अग्रवाल एवं डॉ. रमेश छावरी को केप्टन ऑफ इंडस्ट्री अवार्ड प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने काफी टेबल बुक मेन ऑफ मिटल का लोकार्पण किया। इस मौके पर दैनिक जागरण दिल्ली और मध्यप्रदेश–छत्तीसगढ़ नई दुनिया ग्रुप के प्रभारी श्री दिनेश गुप्ता उपस्थित थे।

धान उत्पादक किसानों को 'जस्ट-इन-टाइम' एप से 878 करोड़ का भुगतान

955 खरीदी केन्द्रों पर 20 जनवरी तक होगा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन

भोपाल। प्रदेश के 30 धान उत्पादक जिलों में 955 खरीद केन्द्रों पर पिछले 2 दिसम्बर से किसानों से समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह खरीदी 20 जनवरी 2020 तक जारी रहेगी।

संचालक खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री अविनाश लवानिया ने बताया कि अभी तक उपार्जित 5 लाख 74 हजार 222 मेट्रिक टन धान की कुल समर्थन मूल्य राशि 1042 करोड़ में से 85 प्रतिशत अर्थात 878 करोड़ का भुगतान किसानों के बैंक खातों में ''जस्ट–इन–टाइम'' एप के माध्यम से किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि ई–उपार्जन पोर्टल पर 5 लाख 43 हजार 062 धान उत्पादक किसानों द्वारा पंजीयन कराया गया। इनमें से एक लाख 79 हजार 295 किसान उपार्जन केन्द्रों पर अपना 10.43 लाख मेट्रिक टन धान समर्थन मूल्य पर विक्रय के लिए पहुँचे।

श्री अविनाश लवानिया ने कहा कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड अनुसार एफ. ए. क्यू. धान की खरीदी की जा रही है। इसके लिए गुणवत्ता का परीक्षण 'सवैयर' एप के माध्यम से ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खरीदी केन्द्रों से कुल उपार्जित धान में से 8 लाख 16 हजार 517 मेट्रिक टन अर्थात 78: धान गोदामों में पहुँचाई जा चुकी है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। जिला और संचालनालय स्तर से पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है।

उद्योगों के लिये स्थायी निवासियों को 70% रोजगार देना अनिवार्य

भोपाल। राज्य शासन ने उद्योग सवंर्धन नीति में नवीन संशोधन/प्रावधान करते हुए औद्योगिक इकाइयों को अतिरिक्त सुविधाएँ देने का निर्णय लिया है। साथ ही, औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के स्थायी निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाना अनिवार्य किया गया है।

प्रदेश में जीएसटी व्यवस्था लागू होने से वृहद श्रेणी के उद्योगों को देय टैक्स सहायता निरंतर दिये जाने के संबंध में प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश की नई सरकार ने औद्योगिक प्रयोजन के लिये आपसी सहमति से निजी भूमि अर्जन के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी भी लागू कर दी है।

राज्य सरकार ने जवाहर लाल नेहरू बंदरगाह मुम्बई को इन्दौर से रेल मार्ग द्वारा जोड़ने के लिये इक्विटी अंशदान के रूप में 15 प्रतिशत की सहभागिता सुनिश्चित की है। इसमें इंदौर से मनमाड़ तक रेल परियोजना का क्रियान्वयन होगा। परियोजना से प्रदेश में उत्पादित माल का परिवहन सुगम हो सकेगा। औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों में रूफटॉफ पर सौर फोटोवोल्टाईक पावर प्लांट के माध्यम से हरित एवं सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया गया है। इसके पहले चरण में मंडीदीप और पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य

उज्जैन में स्व–सहायता समूह की सदस्य महिलाओं को हितलाभ वितरित

भोपाल। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री जयवर्द्धन सिंह ने उज्जैन में डे–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अन्तर्गत महिला स्व–सहायता समूह के सदस्यों को हितलाभ वितरित किये। उन्होंने नगर निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं में चयनित 143 हितग्राहियों को 95 लाख 62 हजार रूपये के चेक वितरित किये। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार का मुख्य उद्देश्य है।

मंत्री श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का उद्देश्य शहर में स्व–रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है।

उन्होंने बताया कि योजना में स्व–सहायता समूहों को 10 हजार से लेकर एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। श्री सिंह ने कहा कि स्व–सहायता समूहों में अधिक से अधिक महिलाओं को जोड़ें, जिससे वे आत्म–निर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह उज्जैन में भी इच्छुक महिलाओं को ई–रिक्शा दिये जायेंगे।

कार्यक्रम में महापौर श्रीमती मीना जोनवाल, नगर निगम अध्यक्ष श्री सोनू गेहलोत और अन्य जन–प्रतिनिधियों ने भी विचार व्यक्त किये।

पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा में परस्पर सहयोग कर सकते हैं मंगोलियाई प्रांत और मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ से मंगोलियाई प्रतिनिधि–मंडल की भेंट

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने मंत्रालय में मंगोलिया के प्रतिनिधि–मंडल से भेंट के दौरान कहा कि मंगोलिया प्रांत और मध्यप्रदेश मिलकर कई क्षेत्रों, विशेषकर सांस्कृतिक आदान–प्रदान, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और मंगोलिया के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में दावोस में उनकी मंगोलिया के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई थी। मंगोलिया के पर्यटन परिदृश्य की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें पर्यटन की संभावनाएं बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मंगोलिया अपने नागरिकों की सादगी और मित्रता के लिए प्रसिद्ध है।

श्री कमल नाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने के कार्यक्रम में सहयोग देगा। उन्होंने प्रदेश के बौद्ध विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक अध्ययन से दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं। श्री कमल नाथ ने कहा कि आमतौर पर सरकारें एक–दूसरे से जुड़ती हैं, लेकिन लोगों को आपस में जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश, भारत के शिक्षा के केंद्र बिन्दु के रूप में उभर रहा है और मंगोलिया जैसे देशों को शैक्षणिक अवसर प्रदान कर सकता है।

मंगोलिया के चीफ आफ केबिनेट सेक्रेटिएट मंत्री श्री ओयूनरडेन लुवासनमसराल ने प्रतिनिधि–मंडल के अन्य सदस्यों को बताया कि मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ भारत के एक महत्वपूर्ण नेता हैं। उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और बताया कि प्रतिनिधि–मंडल ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि निकट भविष्य में मध्यप्रदेश के साथ पर्यटन, संस्कृति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री को मंगोलिया आमंत्रित किया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि मंगोलिया में भरपूर प्राकृतिक संसाधन हैं। मध्यप्रदेश पारंपरिक दवाओं के निर्माण में सहयोग कर सकता है। मध्यप्रदेश शैक्षणिक सुविधाएं भी उपलब्ध करा सकता है क्योंकि यहां कई उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और कौशल विकास केन्द्र हैं।

प्रतिनिधि–मंडल में मंगोलिया के विभिन्न प्रांतों के गवर्नर शामिल थे। संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव संस्कृति श्री पंकज राग, सचिव पर्यटन श्री फैज अहमद किदवई और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

गांगुलपारा में मछुआरों को दिया गया प्रशिक्षण

विधायक श्री कावरे ने मछुआरों को वितरित किये प्रमाण पत्र

बालाघाट। विकासखण्ड बालाघाट के गांगुलपारा जलाशय को 10 वर्षीय पट्टे पर लेकर मत्स्य पालन का कार्य कर रहे है, मछुआ समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अथिति विधायक श्री रामकिशोर कावरे ने किया। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच श्री रमेश राऊत, पूर्व सरपंच श्री राजेन्द्र सिंह ठाकुर, समिति के अध्यक्ष श्री बाबूलाल एवं समिति के समस्त सदस्यगण सम्मानीय सदस्यगण एवं उप संचालक मत्स्योद्योग, बालाघाट श्रीमती शशिप्रभा धुर्वे, विकासखण्ड अधिकारी पूजा रोडगे, सहायक मत्स्य अधिकारी, एवं समस्त कार्यालय के अधिकारीध्कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यक्रम में मछुआरों को विभागीय गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। गांगुलपारा जलाशय में केज के माध्यम फंगेशियस मत्स्य पालन की जानकारी प्रदाय की गई। विधायक श्री रामकिशोर ने समिति द्वारा किये जा रहे मत्स्य पालन के क्षेत्र में समस्त कार्यो की समीक्षा की एवं मछुओं के जीविकापार्जन सुदृढ़ बनाने की अवश्यकता बताई। विधायक श्री कावरे ने शासन द्वारा पर्यटको हेतु संचालित कैटिंन की सराहना की गई। संचालित नया सबेरा योजना में समस्त मछुआ कृषको को पंजीयन हेतु प्रेरित किया गया। जिले में बढते फंगेशियस मत्स्य पालन को लेकर वृहद फीड मिल की स्थापनाध्मत्स्य विक्रय हेतु मत्स्य बाजार की स्थापना करने हेतु प्रयास करने हेतु कहा गया। इस अवसर पर विधायक श्री कावरे द्वारा समिति के वृद्धजनों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया गया है एवं प्रशिक्षणार्थियों को किटबैग एवं प्रमाण पत्र वितरित किये गये।

आदिवासी वर्ग के शैक्षणिक विकास के लिये छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था का सरलीकरण

भोपाल। प्रदेश में आदिवासी वर्ग के शैक्षणिक विकास के लिये छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अब पेपरलेस तरीके से एमपीटास (MPTASS) सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रवृत्ति ऑनलाइन वितरित करना आरंभ किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना में इस व्यवस्था से इस वर्ष 7 हजार 674 शिक्षण संस्थाओं के 2 लाख 76 हजार 163 विद्यार्थियों को करीब 200 करोड़ की छात्रवृत्ति उनके बैंक खातों में पेपरलेस तरीके से एमपीटास (MPTASS) साफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन वितरित की गई है।

प्रदेश के 16 लाख 69 हजार 437 आदिवासी विद्यार्थियों को प्री–मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना का लाभ दिया गया है। इन विद्यार्थियों के बैंक खातों में 136 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि ट्रांसफर की गई है। आदिवासी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति का लाभ दिलाया जाना भी सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2019 में इस योजना में 7 विद्यार्थियों को 82 लाख की छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई गई।

कोचिंग व्यवस्था

आदिवासी वर्ग के युवा देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पा सकें, इसके लिये उन्हें जे.ई.ई., नीट, क्लैट, (JEE, NEET, CLAT) की प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिये राज्य शासन ने निरूशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की है। वर्ष 2019 में 800 विद्यार्थियों की कोचिंग पर 14 करोड़ 50 लाख रूपये खर्च किये गये।

कन्या शिक्षा परिसर

जनजाति वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा और साक्षरता वृद्धि के लिये भी प्रयास शुरू किये गये हैं। इसके लिये प्रदेश में 82 कन्या शिक्षा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। प्रत्येक परिसर की सीट क्षमता 490 है। इस वर्ष परिसर संचालन के लिये करीब 61 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शिक्षा परिसरों और गुरूकुलम का उन्नयन

प्रदेश में इस वर्ष केन्द्र के सहयोग से 9 कन्या शिक्षा परिसरों और 4 गुरूकुलम आवासीय विद्यालयों का एकलव्य विद्यालय में उन्नयन किया गया है। प्रदेश में संचालित 12 एकलव्य आवासीय विद्यालयों में ऑडिटोरियम निर्माण के लिये 18 करोड़ से अधिक राशि मंजूर की गई है। प्रदेश में 13 नये एकलव्य विद्यालय खोले गये हैं। विभाग द्वारा संचालित प्रत्येक हाई स्कूल को 2 लाख और प्रत्येक हायर सेकण्ड्री स्कूल को 5 लाख की राशि अधोसंरचना के विकास के लिये जारी की गई है। विभाग के 119 हायर सेकण्ड्री स्कूलों में से 36 में नवीन शाला भवनों के निर्माण और शेष स्कूलों में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण के लिये 118 करोड़ की राशि जारी की गई है।

इसी के साथ 43 भवनविहीन छात्रावासों में भवन निर्माण के लिये 91 करोड़ 65 लाख की राशि जारी की गई है।

परिवहन माफिया के विरूद्ध की जायेगी कड़ी कार्यवाही : मंत्री श्री राजपूत

सभी चेक–पोस्ट पर बंद होंगी अवैध लिस्टें

भोपाल। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन अधिकारियों से कहा है कि वह बिना किसी डर के परिवहन माफिया के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें। श्री राजपूत प्रशासन अकादमी में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों, निरीक्षकों और फ्लाईंग स्क्वाड की बैठक में राजस्व वसूली की समीक्षा कर रहे थे।

श्री राजपूत ने माफिया की चर्चा करते हुए कहा कि परिवहन विभाग में संगठित माफिया द्वारा अनेक अनियमितताएँ किये जाने की शिकायतें मिल रही थीं, जिनके द्वारा चेक–पोस्टों पर 500–500 अवैध गाड़ियों की निकासी कराने की जानकारी भी प्राप्त हो रही थी। यार्डों में खड़ी गाड़ियों पर करोड़ों का बकाया टैक्स भुगतान नहीं किये जाने की बात मेरे संज्ञान में आई है। श्री राजपूत ने बड़ी संख्या में बहुत–सी वाल्वो ए.सी. बस मालिक द्वारा विभिन्न त्यौहारों पर यात्रियों से निर्धारित किराये से अधिक की राशि वसूल किये जाने तथा रेत और अन्य प्रकार की सामग्री की ओवर–लोडिंग पर भी रोक लगाना बहुत जरूरी है।

31 मार्च तक बकाया 1700 करोड़ परिवहन राजस्व वसूली के निर्देश

राजस्व वसूली में पीछे रहे अधिकारियों की जिलेवार समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि वर्ष 2019–20 में राजस्व वसूली का लक्ष्य 4 हजार करोड़ निर्धारित है। इसमें से अभी तक 2211 करोड़ राजस्व के रूप में प्राप्त हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले ढाई माह में अर्थात 31 मार्च तक 1689 करोड़ रूपये की बकाया वसूली की जाना सुनिश्चित करे। इसके लिये पूरा परिवहन अमला स्वयं नाकों पर उपस्थित रहें। उन्होंने राजस्व वसूली में श्योपुर एवं शिवपुरी जिले के परिवहन अमले की सराहना की जो प्रदेश में अभी तक राजस्व वसूली में प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है।

चिन्हित वाहन मालिकों पर सबसे पहले कार्यवाही

मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि सबसे पहले चिन्हित वाहन मालिकों पर कार्यवाही करें, जिनसे बड़ी राशि की वसूली की जाना है। उन्होंने कहा कि इसके लिये एक विशेष दल गठित करें। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अपने क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे, उन्हे 26 जनवरी को पुरस्कृत किया जायेगा। साथ ही, काम के प्रति लापरवाह अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जायेगी। श्री राजपूत ने कहा कि राजस्व वसूली की रिपोर्ट के आधार पर गोपनीय चरित्रावली में मूल्यांकन दर्ज किया जाएगा।

'वन टाइम सेटलमेंट' योजना में 90 प्रतिशत तक छूट

मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि 'वन टाइम सेटलमेंट' योजना के अंतर्गत छूट का लाभ लेकर वाहन मालिकों को टैक्स भरने का अवसर दिया गया है। इसमें टैक्स में 90 प्रतिशत तक छूट दिये जाने का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दिये। इस योजना से आम जनता एवं सरकार दोनों ही लाभान्वित हो सकेंगे।

समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव परिवहन श्री एस.एन. मिश्रा, परिवहन आयुक्त श्री बी. मधु कुमार और अपर आयुक्त परिवहन भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किसान के खाते में पहुंचेगी अंतर की राशि

20 जिलों को मांग के अनुसार 116 करोड़ की राशि जारी

भोपाल। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में वर्ष 2019–20 में प्याज उत्पादक किसानों को मंडी के क्रय मूल्य और समर्थन मूल्य के अंतर की राशि का भुगतान करने के लिये 20 जिलों को उनकी मांग के अनुरूप 116 करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है। योजना में ई–उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत प्याज उत्पादक किसानों के बैंक खातों में प्याज विक्रय करने पर मूल्य के अंतर की राशि सीधे ट्रांसफर की जायेगी।

प्रदेश की प्याज के लिये अधिसूचित मंडियों में प्याज का मॉडल विक्रय दर रबी प्याज की फसल के लिये निर्धारित अवधि में 800 रूपये प्रति क्विंटल से कम रहता है। इस स्थिति में राज्य सरकार द्वारा प्याज उत्पादक किसानों को अधिसूचित मंडियों में प्याज बेचने पर क्रय मूल्य एवं समर्थन मूल्य 800 रूपये प्रति क्विंटल के अंतर की राशि का भुगतान मुख्यमंत्री प्याज कृषक प्रोत्साहन योजना में किया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा जिला शिवपुरी को 1 करोड़ 14 लाख 90 हजार 440 रूपये, रायसेन 1 लाख 96 हजार 706, आगर–मालवा 7 करोड़ 38 लाख 43 हजार 842 रूपये, उज्जैन 16 करोड़ 32 लाख 89 हजार 197 रूपये, झाबुआ 1 करोड़ 99 लाख 66 हजार 511 रूपये और खरगोन जिले को 3 करोड़ 26 हजार 99 रूपये आवंटित किये गये है।

योजना में जिला खण्डवा को 2 करोड़ 71 लाख 97 हजार 910 रूपये, ग्वालियर 29 हजार 153 रूपये, सीहोर 9 करोड़ 48 लाख 64 हजार 624, रतलाम 1 करोड़ 19 लाख 18 हजार 920 रूपये, नीमच 1 करोड़ 65 लाख 24 हजार 722 रूपये, इंदौर 29 करोड़ 95 लाख 92 हजार 753 रूपये, भोपाल 1 करोड़ 25 लाख 59 हजार 891 रूपये, शाजापुर 9 करोड़ 6 लाख 76 हजार 934 रूपये, मंदसौर 7 करोड़ 79 लाख 18 हजार 28 रूपये, हरदा 12 लाख 54 हजार 76 रूपये, बड़वानी 2 करोड़ 83 लाख 79 हजार 319 रूपये, धार 5 करोड़ 52 लाख 55 हजार 310 रूपये, पन्ना 2 लाख 23 हजार 144 और देवास जिले को 3 करोड़ 67 लाख 25 हजार 397 रूपये बजट आवंटित किये गये हैं। इसके अलावा प्रशासकीय व्यय के लिये 9 लाख 64 हजार रूपये जारी किये गये हैं।

प्रदेश में 802 गांव में हर घर पहुंचा नल से जल

भोपाल। राज्य सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में हर घर नल से जल पहुँचाने के लिये 68 हजार करोड़ लागत की विस्तृत कार्य–योजना लागू की है। योजना में 19 समूह जल योजनाएँ पूर्ण कर 802 गाँव में हर घर तक नल से जल पहुँचाना सुनिश्चित किया गया है। इससे लगभग साढ़े 11 लाख से अधिक ग्रामीण जनसंख्या लाभान्वित हुई है।

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री संजय कुमार शुक्ला ने बताया कि समूह नल–जल की करीब 6672 करोड़ लागत की 39 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है, जो अगले दो साल में पूरा किया जायेगा। इससे 6091 गाँव की लगभग 64 लाख आबादी को घर में ही नल से पेयजल मिलेगा। श्री शुक्ला ने बताया कि प्रदेश के 14 हजार 510 गाँव की एक करोड़ आबादी को पेयजल सुलभ कराने के लिये 22 हजार 484 करोड़ लागत की 45 समूह जल–प्रदाय योजनाओं की डीपीआर तैयार कर ली गई है।

ग्रामीण अंचल में 6 हजार से अधिक हैण्डपम्प स्थापित

प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया कि पिछले एक साल में ग्रामीण अंचल में 6 हजार से ज्यादा हैण्डपम्प स्थापित किये गए है। इस दौरान 600 से अधिक नवीन नल–जल योजनाओं के कार्य पूर्ण कर ग्रामीण अंचल में पेयजल प्रदाय प्रारंभ कराया गया है। साथ ही, 6700 से अधिक सिंगल फेस मोटर पम्प स्थापित किये गये हैं।

आजीविका मेला कार्यक्रम का हुआ आयोजन

सीधी। नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा डे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत आजीविका मेला कार्यक्रम का आयोजन निकाय के नवीन सभाकक्ष में किया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने भोपाल से नगरीय विकास एवं आवास विभाग के मंत्री श्री जयवर्धन सिंह के उद्बोधन का सीधा प्रसारण देखा सुना। इसके पूर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी डॉ. अमर सिंह परिहार द्वारा समस्त अतिथियों एवं उपस्थित हितग्राहियों को योजना के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सीधी में गठित स्व सहायता समूह की महिलाओं एवं शहर के पथ विक्रेता, शासन द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना के हितग्राही एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले हितग्राहियों ने भाग लिया। आजीविका मेला कार्यक्रम के तहत 12 स्व सहायता समूहों को रिवाल्विंग फंड की राशि 10 हजार रूपये के मान से प्रदान की गई।

सहकारिता मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह जी द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन

इंदौर। म.प्र. शासन के सहकारिता, संसदीय कार्य एवं सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री डॉ. गोविन्द सिंह जी द्वारा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र इंदौर में सौजन्य भेंट दी एवं प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण किया।

इस अवसर पर म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन द्वारा मंत्री जी का स्वागत किया गया व प्रशिक्षण केन्द्र की योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री जी ने सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की भूमि एवं किले का निरीक्षण किया एवं केन्द्र में चल रहे सहकारिता निरीक्षकों हेतु एच.डी.सी.एम सत्र के प्रशिक्षणार्थियों से चर्चा की।

कार्यक्रम में शहर के पूर्व विधायक श्री अश्विन जोशी, म.प्र. कांग्रेस के महासचिव एवं प्रवक्ता श्री के.के. मिश्रा, समाजवादी नेता श्री रामबाबू अग्रवाल, सहकारिता विभाग के अपर आयुक्त सहकारिता श्री आर.सी. घिया, संयुक्त आयुक्त, सहकारिता श्री अरविंद सिंह सेंगर, श्री प्रदीप नीखरा, प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक, संयुक्त आयुक्त सहकारिता श्री जगदीश कन्नौज एवं सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रभारी प्राचार्य श्री निरंजन कुमार कसारा, श्री के.एल. राठौर सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

इंदौर जिले में चलाये जा रहे शून्य शक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा : सहकारिता मंत्री

इंदौर। सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को पुनः पुनर्जीवित किया जाएगा। मध्यप्रदेश में सहकारिता के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया जाएगा। श्री गोविन्द सिंह ने कहा कि इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये चलाया जा रहा शून्य शक्ति अभियान सराहनीय प्रयास है। यह अभियान पूरे प्रदेश में लागू होगा।

मंत्री श्री गोविंद सिंह सांवेर में किसान समृद्धि केंद्र के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने की। इस अवसर पर विधायक श्री रामलाल मालवीय, श्री महेश परमार, श्री सदाशिव यादव, के.के. मिश्रा, श्री भारत सिंह चौहान, श्री हुकम सिंह सांखला, श्री दिलीप चौधरी, श्री राम सिंह पारिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मंत्री श्री गोविंद सिंह ने कहा कि सहकारिता जरूरतमंद एवं गरीबों को संगठित कर उनके उत्थान का बेहतर माध्यम है। सहकारिता के क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। सहकारिता का विस्तार गांव–गांव तक किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को खाद–बीज और अन्य कृषि आदान रियायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को कृषि यंत्र भी रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा किसान समृद्धि केंद्र के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है जिसके माध्यम से किसानों को उनकी पसंद के अनुसार कृषि आदान उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

इंदौर जिले में चल रहे शून्य शक्ति अभियान की सराहना

मंत्री श्री गोविंद सिंह ने इंदौर जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिये कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव की पहल पर चलाए जा रहे शून्य शक्ति अभियान की सराहना की। श्री गोविन्द सिंह ने कहा कि इस तरह का अभियान पूरे प्रदेश में चलाये जाने की जरूरत है। इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान किसानों के हित में है। इस अभियान के लिये यहां के अधिकारी और जनप्रतिनिधि बधाई के पात्र हैं। यह अभियान जरूरतमंद किसानों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। किसानों की छोटी–मोटी राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण में मददगार है। यह बहुत पुण्य का कार्य है। उन्होंने इस अभियान के तहत लाभान्वित किसानों को ऋण पुस्तिका, खसरे की प्रति, नकल आदि वितरित किये। इस अभियान के तहत सांवेर तहसील में एक हजार 200 अविवादित राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि सहकारिता के आंदोलन को जन–जन तक पहुंचाया जाएगा। सहकारिता के माध्यम से कृषि एवं गांव का विकास निर्भर है। सहकारिता का क्षेत्र जितना विस्तारित और मजबूत होगा उतना ही गांव एवं कृषि का विकास होगा। ग्रामीणों का उत्थान भी होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी का बड़ा निर्णय लेकर उसका चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। प्रथम चरण में 50 हजार रूपये तक के ऋण माफ किए गए हैं। इसके बाद दूसरे चरण में अब 50 हजार रूपये से लेकर एक लाख रूपये तक का तथा तीसरे चरण में एक लाख रूपये से दो लाख रूपये तक का कर्जा माफ होगा। कोई भी किसान छूटेगा नहीं। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम मिले इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक कारगर कदम उठाए गए हैं। किसानों को बिजली के बिलों में रियायत दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत अब तक 40 मिलावट खोरों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा 106 एफ आई आर दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक शिक्षित और स्वस्थ बने यह हमारा संकल्प है। श्री सिलावट ने कहा कि नर्मदा गंभीर लिंक परियोजना से सांवेर तहसील के 43 गांवों में सिंचाई के साथ ही पेयजल की सुविधा भी ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को श्री भारत सिंह चौहान, श्री सदाशिव यादव, श्री के.के. मिश्रा आदि ने भी सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कृषि कर्मण पुरस्कार मिलने पर दी किसानों, कृषि अमले को बधाई

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने गेहूँ और दालों के उत्पादन में मध्यप्रदेश को उत्कृष्टता के लिए कृषि कर्मण अवार्ड मिलने पर किसानों और विशेष रूप से प्रगतिशील किसानों को बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसान अपनी मेहनत से प्रदेश को कृषि कर्मण पुरस्कार दिला रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री कमल नाथ ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को हर कदम पर सहयोग देने को तत्पर है। संकट के समय में भी मदद के लिए हमेशा उनके साथ है। उन्होंने कहा कि किसानों पर दो लाख रुपये तक का कर्ज माफ कर सरकार ने किसानों की मेहनत का सम्मान किया है।

मुख्यमंत्री कहा कि कृषि कर्मण पुरस्कार के असली हकदार मध्यप्रदेश के मेहनती किसान हैं। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग सहित सहयोगी विभागों के मैदानी अमले को भी बधाई दी है, जिसने हर पल किसानों को सहयोग दिया है।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक दिनेशचंद्र शर्मा द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई–8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : दिनेशचंद्र शर्मा
डाक पंजीयन क्रमांक – म.प्र./भोपाल/357/2018-20 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2725518, फैक्स : 0755-2726160 इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।